वित्तीय नीति
(Fiscal Policy)

मुद्रा-स्फीति का नियंत्रण करने के लिए मौद्रिक नीति के साथ साथ वित्तीय नीति के कार्यान्वयन का भार देश की सरकार के ऊपर होता है। मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए वित्तीय नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय आते हैं:-

1. सरकारी व्यय (Government spending):- मुद्रा-स्फीति के समय लोगों की निजी व्यय (Private spending) में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अतः सरकार को चाहिए कि निजी व्यय में होने वाली वृद्धि के प्रभावों को कम करने के लिए सरकारी व्यय में कमी करे। सरकारी व्यय में कमी करने से मूल्यों में गिरावट आती है। लेकिन इस संबंध में निम्नलिखित तीन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है — (i) मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए सरकारी व्यय में अत्यधिक कटौती नहीं करनी चाहिए अन्यथा मंदी का भय बना रहता है। (ii) मुद्रा-स्फीति को रोकने की अल्पकालीन नीति एवं सार्वजनिक विनियोग की दीर्घकालीन नीति के बीच विरोध हो सकता है अतः दीर्घकालीन विनियोग कार्यक्रमों पर किये जाने वाले व्यय में भी कटौती करना अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं होता। (iii) युद्धकाल में भी देश की सुरक्षा के हित में सरकारी युद्धकालीन व्यय में कटौती नहीं की जा सकती। फिर भी इन अपवादों को छोड़कर सरकारी व्यय में की जाने वाली कमी मुद्रा-स्फीति को रोकने में सहायक होती है।

2. कर (Taxes):- यदि वस्तुओं की ~~अप्राप्य~~ पूर्ति की हुई हो तो जनता की व्यय-योग्य आय (Disposable Income) और मुद्रा स्फीति की तीव्रता को निर्धारित करने वाला तत्व कर (Tax) होता है। अतः मुद्रा-स्फीति के समय करारोपण के द्वारा जनता की व्यय योग्य आय में कमी की जानी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान कर के ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाय, करों में कमी नहीं की जाय तथा नये कर लगाये जाय अथवा वर्तमान करों की दरों में वृद्धि की जाय ताकि लोगों की व्यय-योग्य आय में कमी करके मुद्रा-स्फीति पर काबू पाया जा सके। मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए प्रायः सबसे उपयुक्त कर व्यक्तिगत आयकर (Personal Income Tax) होता है जिसकी दरों में वृद्धि कर मूल्यों को बढ़ने से रोका जा सकता है।

Scanned with CamScanner

3. सार्वजनिक ऋण (Public Borrowing) :- सार्वजनिक अथवा सरकारी ऋणो मे वृद्धि करके भी मुद्रा - स्फीति का नियंत्रण किया जा सकता है। इससे जनता के हाथो की क्रय शक्ति सरकार के पास चली आती है लोग कम व्यय करते है और मूल्यो मे कमी होती है। सार्वजनिक ऋण भी दो प्रकार का होता है - ऐच्छिक एवं अनिवार्य। सार्वजनिक ऋण प्रायः ऐच्छिक ही होता है और यह जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि स्फीतिक दबावो को कम करने के लिए इससे सरकार को पर्याप्त रकम प्राप्त नही होती। अतः कालान्तर मे और विशेषकर युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए सरकार को अनिवार्य ऋणो अथवा अनिवार्य बचत (Compulsory Saving) का सहारा लेना पड़ता है। इसके अन्तर्गत लोगो के वेतन एवं मजदूरी मे से एक निश्चित प्रतिशत अनिवार्यतः काट लिया जाता है और मुद्रा - स्फीति की समाप्ति के बाद उस रकम को ब्याज सहित लौटा दिया जाता है।

(4) ऋण प्रबन्ध (Debt Management) :- सरकार को सार्वजनिक ऋण (Public Debt) का प्रबन्ध इस प्रकार करना चाहिए ताकि मुद्रा की पूर्ति मे कमी की जा सके और साख के विस्तार को रोका जा सके। इसके लिए बैंको के ऋणो का भुगतान बजट आधिक्य (budgetary surplus) से किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि व्यवसायिक बैंको के पास सार्वजनिक ऋण का प्रतिनिधित्व करती हुई जबतक सरकारी प्रतिभूतियाँ रहेगी तबतक वे उन्हे खुले बाजार मे बेचकर अतिरिक्त साधन प्राप्त कर सकते है और साख का विस्तार कर सकते है। इससे मुद्रास्फीति को रोकने मे कठिनाई होगी। अतः बजट आधिक्य से बैंको के ऋणो का भुगतान कर मुद्रा - स्फीति को रोका जा सकता है।

(5) स्वर्ण - निष्क्रीयकरण (Gold sterilisation) :- यदि देश मे स्वर्ण के प्रवाह (gold inflow) मे वृद्धि होने से मुद्रा-स्फीति उत्पन्न हो रही हो तो सरकार को चाहिए कि स्वर्ण को निष्क्रिय बना दे ताकि बैंक अधिक स्वर्ण प्राप्त कर अपने कोष मे वृद्धि न कर सके और साख का प्रसार न कर सके। स्वर्ण को निष्क्रिय करने के लिए सरकार सोने की खरीद का भुगतान केन्द्रीय बैंक मे रखी गई अपनी जमा से नही करके सदस्य बैंको के पास जमा सरकारी प्रतिभूतियो की बिक्री से प्राप्त धन से करती है। इस प्रकार स्वर्ण का निष्क्रीयकरण करके मुद्रा - स्फीति पर नियंत्रण रखा जा सकता है।

Scanned with CamScanner

(6) अतिमूल्यन (overvaluation):- कोई देश अपनी मुद्रा का अतिमूल्यन करके भी मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण कर सकता है। अतिमूल्यन (overvaluation) का मतलब विदेशी मुद्रा (Foreign currency) की तुलना में देशी मुद्रा को अधिक खर्चीला (expensive) बनाना या उसके मूल्य में वृद्धि करना है।

Scanned with CamScanner